घरेलू मांग बनेगी अर्थव्यवस्था की ताकत

वर्ष 2026-27 में जीडीपी ग्रोथ 7.2 प्रतिशत रहने का अनुमान

नई दिल्ली, 6 जनवरी. वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत की अर्थव्यवस्था को आने वाले वर्षों में घरेलू मांग और बैंक कर्ज से मजबूती मिलने की उम्मीद है. एसबीआई म्यूचुअल फंड की रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त वर्ष 2026-27 में आर्थिक वृद्धि का आधार खपत और कर्ज रहेगा.

नियंत्रित महंगाई, स्थिर मौद्रिक नीति और चुनिंदा सेक्टरों में निवेश से भारत की ग्रोथ कहानी मजबूत बनी रह सकती है. भारत की अर्थव्यवस्था को वित्त वर्ष 2026-27 में घरेलू खपत और बैंक कर्ज से बड़ा सहारा मिलने की संभावना है. एसबीआई म्यूचुअल फंड की मंगलवार को जारी रिपोर्ट के अनुसार, इस अवधि में देश की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर करीब 7.2 प्रतिशत रह सकती है, जबकि नॉमिनल जीडीपी में लगभग 11 प्रतिशत की बढ़ोतरी का अनुमान है. रिपोर्ट में कहा गया है कि बैंक कर्ज की रफ्तार आने वाले समय में तेज हो सकती है. वित्त वर्ष 2026-27 में कर्ज वृद्धि 13 से 14 प्रतिशत तक रहने की संभावना है. आंकड़ों के मुताबिक, मई 2025 में बैंक कर्ज वृद्धि दर 9 प्रतिशत थी, जो नवंबर 2025 तक बढ़कर 11.4 प्रतिशत हो चुकी है.

> रिपोर्ट के अनुसार, घरेलू परिवारों का कर्ज कंपनियों की तुलना में तेज गति से बढ़ सकता है. जिन क्षेत्रों में कर्ज आधारित खपत और बेहतर उत्पादों की मांग है, वहां मजबूत प्रदर्शन देखने को मिल सकता है. हालांकि, निर्यात अभी भी भारतीय अर्थव्यवस्था की कमजोर कड़ी बना हुआ है, लेकिन राहत की बात यह है कि महंगाई नियंत्रण में बनी हुई है. एसबीआई म्यूचुअल फंड का मानना है कि शेयर बाजार में 2025 के दौरान दिखा रुझान 2026 में भी जारी रह सकता है. उभरते बाजारों के शेयर और औद्योगिक वस्तुएं बेहतर प्रदर्शन कर सकती हैं.

अमेजन पे ने भारत में सावधि जमा की शुरुआत की

नयी दिल्ली, 06 जनवरी. भुगतान सुविधा प्लेटफॉर्म अमेजन पे ने भारत में अपनी सेवाओं का विस्तार करते हुए मंगलवार को सावधि जमा सुविधा की शुरुआत की घोषणा की. अमेजन पे ने एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि उसने इसके लिए दो प्रमुख गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों श्रीराम फाइनेंस और बजाज फाइनेंस तथा पांच बैंकों शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, साउथ इंडियन बैंक, स्लाइस और उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ रणनीतिक साझेदारी की है. ग्राहक अमेजन पे पर सिर्फ 1,000 रुपये से सावधि जमा खाता खोल सकते हैं. इसके लिए उन्हें संबंधित बैंक में बचत खाता खोलने की जरूरत भी नहीं होगी.

चांदी के दाम ऑल टाइम हाई पर

1.37 लाख पार हुआ सोना

2.45 लाख पर पहुंची चांदी

नई दिल्ली, 06 जनवरी. नए साल की शुरुआत के साथ ही बुलियन बाजार में जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है. चांदी ने इतिहास रचते हुए रुपए 2.45 लाख प्रति किलो का ऑल टाइम हाई छू लिया है, जबकि सोना भी रुपए1.37 लाख के करीब पहुंच गया है. कमजोर डॉलर, वैश्विक तनाव और बढ़ती औद्योगिक मांग ने कीमती धातुओं की कीमतों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया है.

देश के बुलियन बाजार में तेजी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. आज यानी 6 जनवरी को चांदी ने नया इतिहास बनाते हुए 2,44,788 प्रति किलो का ऑल टाइम हाई दर्ज किया. इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार एक ही दिन में चांदी 7,725 रुपए महंगी हो गई. इससे पहले इसका भाव 2,37,063 प्रति किलो था. वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत भी 741 रुपए बढ़कर 1,36,909 तक पहुंच गई. हालांकि सोने ने अपना ऑल टाइम हाई 29 दिसंबर 2025 को रुपए 1,38,161 पर बनाया था.

> आंकड़ों के मुताबिक, साल 2025 में सोना कुल ?57,033 यानी करीब 75 प्रतिशत महंगा हुआ. 31 दिसंबर 2024 को सोने का भाव ?76,162 था, जो 31 दिसंबर 2025 तक बढ़कर ?1,33,195 हो गया. वहीं चांदी ने तो निवेशकों को चौंकाते हुए 167 प्रतिशत की छलांग लगाई. एक साल में चांदी ?1,44,403 महंगी होकर ?2,30,420 प्रति किलो तक पहुंच गई. विशेषज्ञों के अनुसार सोने में तेजी के तीन बड़े कारण हैं—अमेरिका में ब्याज दरों में कटौती से डॉलर का कमजोर होना, रूस-यूक्रेन युद्ध समेत वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव और चीन जैसे देशों द्वारा रिजर्व बैंक में बड़े पैमाने पर सोने की खरीद.

एमजी विंडसर बनी भारत की नंबर-1 ईवी

गुरुग्राम, 06 जनवरी. जेएसडब्लू एमजी मोटर इंडिया ने साल 2025 में एमजी विंडसर की 46,735 यूनिटें बेचीं. एक ही ईवी मॉडल के लिए यह उपलब्धि हासिल करने वाली यह पहली ऑटो निर्माता कंपनी है. मुख्य झलकियाँ: एमजी विंडसर ने साल 2025 में सर्वाधिक माह-दर-माह वृद्धि दर्ज की और प्रतिमाह लगभग 4,000 कारें बेचीं.

जेएसडब्लू एमजी मोटर इंडिया की इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री साल 2024 के मुकाबले साल 2025 में 111प्रतिशत बढ़ी. एमजी विंडसर की सेल साल 2024 की चौथी तिमाही के मुकाबले साल 2025 की चौथी तिमाही में 20प्रतिशत से अधिक बढ़ी. जेएसडब्लू एमजी मोटर इंडिया की एमजी विंडसर साल 2025 में भारत की सबसे अधिक बिकने वाली इलेक्ट्रिक कार बन गई है. एमजी विंडसर ने ऑटोमोटिव बाजार में काफी मजबूत मूल्य प्रस्ताव पेश किया है तथा यह अपने सेगमेंट में मार्केट लीडर के रूप में स्थापित हो गई है. साल 2025 में इस कार की 46,735 यूनिटें बिकी हैं.

एमजी विंडसर ने सफलता का एक ऐसा मानक स्थापित कर दिया है, जो इससे पहले भारत के इलेक्ट्रिक कार बाजार में अभी तक कोई भी ऑटो निर्माता कंपनी हासिल नहीं कर पाई है. एमजी विंडसर भारत की सबसे अधिक बिकने वाली इलेक्ट्रिक कार है. यह कार परिवारों को बहुत अधिक आकर्षित करती है. इसमें काफी विशाल केबिन स्पेस, बेहतर कम्फर्ट और शानदार फीचर्स मिलते हैं. ड्राईविंग के मामले में यह असाधारण अनुभव प्रदान करती है. आज यह भारत की सबसे अधिक चहेती और सबसे अधिक पुरस्कार जीतने वाली इलेक्ट्रिक कार है. इस उपलब्धि के बारे में अनुराग महरोत्रा, मैनेजिंग डायरेक्टर, जेएसडब्लू एमजी मोटर इंडिया ने कहा, "विंडसर आधुनिक समय का एक बेहतरीन ऑटोमोटिव चमत्कार है, जिसकी टेक्नोलॉजी तथा व्यवहारिक और भविष्य पर केंद्रित डिजाईन ने इलेक्ट्रिक कारों के सेगमेंट में नए मानक स्थापित कर दिए हैं.

भारत की सर्विस इकॉनमी में मजबूती

एचएसबीसी पीएमआई दिसंबर में 58 पर मजबूत

पीएमआई 50 से ऊपर विस्तार जारी

नई दिल्ली, 6 जनवरी. दिसंबर में भारत के सेवा क्षेत्र ने एक बार फिर मजबूती दिखाई है. एचएसबीसी इंडिया सर्विसेज पीएमआई भले ही नवंबर के मुकाबले थोड़ा घटा हो, लेकिन यह अब भी विस्तार के मजबूत संकेत दे रहा है.

नए घरेलू और निर्यात ऑर्डर, नियंत्रित महंगाई और स्थिर मांग ने सेवा क्षेत्र को सहारा दिया है, हालांकि साल के अंत में रफ्तार कुछ धीमी हुई है. भारत के सेवा क्षेत्र की वृद्धि दिसंबर 2025 में मजबूत बनी रही, हालांकि इसकी गति में मामूली नरमी देखने को मिली है. एसएंडपी ग्लोबल द्वारा तैयार एचएसबीसी इंडिया सर्विसेज पीएमआई बिजनेस एक्टिविटी इंडेक्स नवंबर के 59.8 से घटकर दिसंबर में 58 पर आ गया. इसके बावजूद यह सूचकांक 50 के स्तर से काफी ऊपर बना हुआ है, जो अर्थव्यवस्था में निरंतर विस्तार का संकेत देता है.

रिपोर्ट में कहा गया है कि दिसंबर का पीएमआई स्तर अपने लंबे समय के औसत 55 से भी ऊपर रहा, जिससे यह स्पष्ट होता है कि सेवा क्षेत्र की बुनियाद मजबूत है. हालांकि, पिछले 11 महीनों की तुलना में नए काम और उत्पादन की रफ्तार कुछ धीमी पड़ी है. इसका एक कारण यह भी बताया गया है कि कई कंपनियों ने फिलहाल नई भर्तियों पर रोक लगा दी है. इसके बावजूद नए काम और निर्यात से जुड़े ऑर्डरों में अच्छी बढ़ोतरी दर्ज की गई है.

शेयर बाजारों में लगातार दूसरे दिन गिरावट जारी

मुंबई, 06 जनवरी. विदेशों से मिले सकारात्मक संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजारों में मुनाफावसूली के कारण मंगलवार को लगातार दूसरे दिन गिरावट देखी गयी.

बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 376.28 अंक टूटकर 85,063.34 अंक पर बंद हुआ. टाटा समूह की रिटेल कंपनी ट्रेंट का शेयर 8.5 प्रतिशत से अधिक लुढ़क गया. रिलायंस इंडस्ट्रीज में भी मुनाफावसूली का दबाव रहा और इसका शेयर करीब 4.5 प्रतिशत टूटा. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की निफ्टी-50 सूचकांक 71.60 अंक यानी 0.27 फीसदी नीचे 26,178.70 अंक पर बंद हुआ. मझौली कंपनियों के सूचकांक निफ्टी मिडकैप-50 में 0.06 फीसदी और छोटी कंपनियों के निफ्टी स्मॉलकैप-100 सूचकांक में 0.22 प्रतिशत की गिरावट रही. तेल एवं गैस, रसायन और मीडिया सूचकांकों में गिरावट रही. स्वास्थ्य, फार्मा, आईटी और सार्वजनिक बैंकों के समूहों के सूचकांक बढ़त में बंद हुए. सेंसेक्स की कंपनियों में ट्रेंट और रिलायंस इंडस्ट्रीज के अलावा आईटीसी और कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर 2.02 प्रतिशत टूटे.

एनबीएफसी को आरबीआई की सख्त सलाह

एसेट क्वालिटी और अंडरराइटिंग पर जोर

जिम्मेदार लेंडिंग अपनाने के निर्देश

मुंबई, 06 जनवरी. भारतीय रिजर्व बैंक ने नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों की बढ़ती भूमिका को देखते हुए सतर्कता बढ़ा दी है. मजबूत आर्थिक वृद्धि और तेज कर्ज विस्तार के बीच आरबीआई गवर्नर ने एनबीएफसी कंपनियों को अंडरराइटिंग मानकों और एसेट गुणवत्ता पर कड़ी निगरानी रखने की सलाह दी है.

केंद्रीय बैंक ने जिम्मेदार लेंडिंग और ग्राहक हितों को प्राथमिकता देने पर जोर दिया है. भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने सोमवार को चुनिंदा बड़ी नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक कर लोन वितरण में सतर्कता बरतने और एसेट गुणवत्ता पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए. यह बैठक ऐसे समय पर हुई है, जब देश में आर्थिक गतिविधियां तेज हैं और कर्ज की मांग लगातार बढ़ रही है. आरबीआई की ओर से जारी बैठक में सरकारी एनबीएफसी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों और माइक्रोफाइनेंस संस्थानों के एमडी और सीईओ शामिल हुए. गवर्नर ने कहा कि अर्थव्यवस्था में लोन प्रवाह बनाए रखने में एनबीएफसी की अहम भूमिका है, लेकिन इसके साथ मजबूत अंडरराइटिंग स्टेंडर्ड और जोखिम प्रबंधन भी उतना ही जरूरी है.

कच्चा तेल छह महीने में 51 डॉलर तक टूटेगा : एसबीआई

नई दिल्ली, 06 जनवरी. इस साल जून तक अंतरर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल 51 डॉलर प्रति बैरल तक टूट सकता है और रुपया तीन प्रतिशत मजबूत होकर 88 रुपये प्रति डॉलर तक पहुंच सकता है. भारतीय स्टेट बैंक की बाजार अध्ययन इकाई एसबीआई रिसर्च ने सोमवार को एक रिपोर्ट में यह बात कही है.

उसने बताया कि ओपेक प्लस देशों के उत्पादन बढ़ाने के फैसले से आम तौर पर कच्चे तेल की कीमतों में नरमी रही है. बाद में उत्पादन घटाने की रणनीति के बावजूद दाम नहीं बढ़े हैं. साल 2022 से अब तक मध्यम अवधि में मानक ब्रेंट क्रूड और भारतीय बास्केट में कच्चे तेल की कीमत टूटी है. ओपेक प्लस में तेल निर्यातक देशों के संगठन ओपेक के अलाव कुछ गैर-ओपेक तेल निर्यातक देश भी शामिल हैं. रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2026 के लिए ब्रेंट क्रूड का परिदृश्य इसमें गिरावट के संकेत देता है.

यात्री वाहनों की खुदरा बिक्री 44.75 लाख पर

नई दिल्ली, 06 जनवरी. देश में यात्री वाहनों की खुदरा बिक्री साल 2025 में 9.7 प्रतिशत बढ़कर 44.75 लाख पर पहुंच गयी.

वाहन डीलर संगठनों के महासंघ फाडा द्वारा मंगलवार को जारी आंकड़ों में बताया गया है कि पिछले साल देश में कुल 2,81,61,228 वाहन बिके जो साल 2024 के मुकाबले 7.71 प्रतिशत अधिक है. इसमें यात्री वाहनों की बिक्री 9.7 फीसदी बढ़कर 44,75,309 इकाई पर पहुंच गयी. दुपहिया की बिक्री 7.24 फीसदी की वृद्धि के साथ 2,02,95,650 इकाई रही. फाडा के अध्यक्ष सी.एस. विग्नेश्वर ने कहा कि साल के दौरान जनवरी-अगस्त की कहानी सितंबर-दिसंबर की कहानी से बिल्कुल अलग रही. पहले आठ महीने में मांग में कुछ खास वृद्धि नहीं हुई, लेकिन वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में अगली पीढ़ी के सुधारों की घोषणा के बाद छोटी कारों, 350सीसी से कम के दुपहिया, तिपहिया और महत्वपूर्ण वाणिज्यिक वाहनों की कीमतों में गिरावट से अंतिम चार महीने में वाहन उद्योग ने जबरदस्त उड़ान भरी. खास बात यह रही कि यात्री वाहनों (कार, उपयोगी वाहन और वैन) के खंड में ग्रामीण क्षेत्रों की खुदरा मांग शहरी क्षेत्रों के मुकाबले कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ी. शहरी क्षेत्र की वृद्धि दर 8.08 प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्र की 12.31 प्रतिशत रही.

समाचार विशेष

बागी नेताओं के लिए कांग्रेस का 'चक्रव्यूह'

नई दिल्ली. असम विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने एक ऐसी धांसू रणनीति तैयार की है, जिसे जानकर हर कोई हैरान है. अक्सर देखा जाता है कि चुनाव के समय टिकट न मिलने पर नेता अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल देते हैं, लेकिन अब ऐसा करना मुमकिन नहीं होगा. कांग्रेस आलाकमान ने बगावत को जड़ से खत्म करने के लिए एक विशेष 'अंडरटेकिंग' का नियम बनाया है. इस नई व्यवस्था के तहत टिकट की दावेदारी पेश करने से पहले नेताओं को एक कसम खानी होगी.

पार्टी ने टिकट चाहने वालों के लिए एक खास एप्लीकेशन फॉर्म जारी किया है, जिसे भरना हर दावेदार के लिए अनिवार्य है. लेकिन यह फॉर्म सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, बल्कि इसमें कड़े नियम और शर्तें शामिल हैं. फॉर्म भरने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि टिकट पक्का हो गया. पार्टी सभी आवेदनों की बारीकी से जांच करेगी और जो उम्मीदवार सबसे मजबूत लगेगा, उसी पर भरोसा जताएगी. खास बात यह है कि फॉर्म भरते समय ही नेता को लिखित में वादा करना होगा.

50 हजार रुपये और वफादारी का टेस्ट- अगर किसी नेता को लगता है कि वह आसानी से दावेदारी जता देगा, तो उसे अपनी जेब भी ढीली करनी पड़ेगी. यह आवेदन फॉर्म मुफ्त में उपलब्ध नहीं है. इसके साथ दावेदार को 50 हजार रुपये का डिमांड ड्राफ्ट लगाना होगा. जो भी नेता इन सख्त शर्तों को मानने के लिए तैयार है, उसे 20 जनवरी तक हर हाल में अपना आवेदन जमा करना होगा. कांग्रेस ने यह साफ संदेश दे दिया है कि अनुशासन और पार्टी के प्रति वफादारी ही टिकट पाने की सबसे बड़ी योग्यता मानी जाएगी.

> **100 सीटों पर वार, बाकी पर यार**
>
> असम की कुल 126 विधानसभा सीटों के गणित को लेकर भी स्थिति साफ हो चुकी है. कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि वह करीब 100 सीटों पर खुद अपने उम्मीदवार उतारेगी और बाकी सीटें गठबंधन के छोटे दलों के लिए छोड़ी जाएंगी. अक्सर एक सीट पर कई दावेदार होने से नाराजगी बढ़ती है और खेल बिगड़ता है. इसलिए, आलाकमान ने यह सुनिश्चित किया है कि जो नेता टिकट से वंचित रह जाएं, वे 'अंडरटेकिंग' के कारण बगावत न कर सकें और पार्टी एकजुट होकर चुनाव लड़ सके.

भागवत क्यों दूरी दिखा रहे भाजपा से

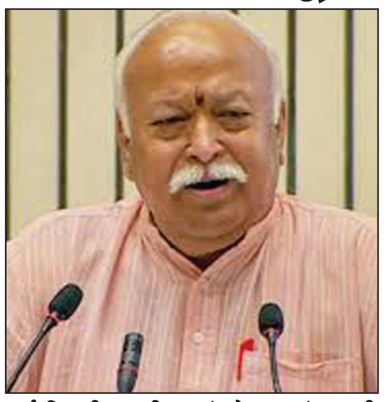

नई दिल्ली. राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ यानी आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने एक बार फिर संघ और भाजपा की दूरी बताई है. यह हैरानी की बात है कि बिना किसी संदर्भ के अचानक उन्होंने कहना शुरू किया है कि भाजपा के नजरिए से आरएसएस को देखने की जरुरत नहीं है. यह बात पिछले दिनों उन्होंने कोलकाता में कही थी, जहां वे संघ के एक सौ साल पूरे होने के मौके पर चल रहे व्याख्यान की शृंखला में भाषण देने गए थे.

अब दो हफ्ते के भीतर उन्होंने फिर कहा है कि भाजपा के नजरिए से संघ को देखने की जरुरत नहीं है. उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा या विश्व हिंदू परिषद या दूसरे संगठन जो हैं उनके काम करने का तरीका अपना अपना है लेकिन संघ तो सिर्फ राष्ट्र निर्माण का काम करता है और लोगों को जोड़ने का काम करता है. एक तरह से उन्होंने विश्व हिंदू परिषद से भी संघ की दूरी दिखाई.

सवाल है कि ऐसा क्यों है? क्या संघ प्रमुख किसी वजह से नाराज हैं? उनके इस तरह के बयान भाजपा के नए कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन की नियुक्ति के बाद आने शुरू हुए हैं.

> इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि भाजपा की केंद्र सरकार की कई नीतियों या राज्यों के कामकाज से संघ के लोग खुश नहीं हैं. उनको यह फीडबैक है कि व्यापक रूप से हिंदू समाज में अब पहले जैसा उत्साह का भाव नहीं है. उनको लग रहा है कि भाजपा भी दूसरी पार्टियों की तरह काम कर रही है. इसलिए हो सकता है कि संघ को इस तरह के बयान देने की मजबूरी हुई हो. विश्व हिंदू परिषद और कुछ दूसरे संगठनों की ओर से हिंसा और मारपीट या मोरल पुलिसिंग जैसे कामों से भी आरएसएस को अलग दिखाने के लिए ऐसा बयान दिया गया हो सकता है.

तभी कहा जा रहा है कि उनकी नाराजगी इस वजह से हो सकती है. जानकार सूत्रों का कहना है कि संघ की ओर से जिन नामों की संभावना पर विचार किया जा रहा था कि उसमें नितिन नबीन का नाम नहीं था.

मौसम नूर को कांग्रेस में क्या मिलेगा

कोलकाता. तृणमूल कांग्रेस छोड़ कर वापस में कांग्रेस में शामिल हुईं मौसम नूर की राजनीति सांसद और विधायक से आगे की नहीं है. कांग्रेस के नेता भले इसे बड़ी उपलब्धि बताएं लेकिन सबको पता है कि उनकी राजनीति सांसद और विधायक बनने की है. उनको लगने लगा था कि अप्रैल 2026 में उनकी राज्यसभा समाप्त होगी तो ममता बनर्जी फिर से राज्यसभा नहीं भेजेंगी.

ऐसे ही कारण से उन्होंने 2019 के चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस भी छोड़ी थी. वे 2009 और 2014 में लगातार दो बार मालदा उत्तरी सीट से लोकसभा का चुनाव जीती थीं. लेकिन 2019 के चुनाव से पहले उनको लगा कि वे कांग्रेस की टिकट पर नहीं जीत सकेंगी तो तृणमूल में चली गईं.

तृणमूल कांग्रेस ने उनको टिकट किया लेकिन वे भाजपा के खगेन मुर्मू से हार गईं, जिनको उन्होंने दो बार हराया था. बंगाल कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि इस बार मौसम नूर को लग रहा है कि ममता बनर्जी उनको राज्यसभा भी नहीं भेजेंगी और लोकसभा की टिकट भी नहीं देंगी.

विशेष नए जनरेशन का भरोसा जीतने की कोशिश

बंगाल से तय होगा भाजपा का भविष्य!

नई दिल्ली. 2025 का साल भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अहम मोड़ पर खड़ा है, खासकर हाल के चुनावी जीतों के बाद. दिल्ली विधानसभा चुनाव में 27 साल बाद मिली जीत और बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में पुनः एनडीए सरकार के गठन के बाद, भाजपा ने यह साबित कर दिया कि वह मजबूत चुनावी रणनीति की सटीकता से सफल हो सकती है.

पिछले वर्ष के चुनावी सफर के बाद, नए साल में भाजपा के सामने कई नई चुनौतियां हैं, जो पार्टी की रणनीति और भविष्य को प्रभावित कर सकती हैं.इस साल दक्षिण भारत में चुनाव होने हैं. तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, असम, और पुडुचेरी में भाजपा को अपना वजूद और राजनीतिक दबदबा कायम रखने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी. खासकर तमिलनाडु और केरल में भाजपा ने अपनी जड़ें स्थापित करने की कोशिशों को तेज किया है. हालांकि पार्टी ने केरल में कुछ सफलता पाई है, फिर भी उसे इन राज्यों में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए लंबा रास्ता तय करना होगा.

बंगाल भाजपा के लिए एक साख का मुद्दा-पश्चिम बंगाल में भाजपा की उम्मीदें पिछले चुनाव में पूरी नहीं हो पाईं, और इस बार यह राज्य भाजपा के लिए एक साख का मुद्दा बन चुका है. गृह मंत्री अमित शाह ने खुद इस राज्य में अभियान की कमान संभाली है, और बांग्लादेशी घुसपैठ और उथलपुथल के मुद्दे पर पार्टी को कितना फायदा मिलता है, यह देखना होगा. असम में भी भाजपा को अपनी सरकार बनाए रखने की चुनौती का सामना करना पड़ेगा, खासकर बांग्लादेशी घुसपैठ और सीमा सुरक्षा के मुद्दों पर पार्टी को निर्णायक जवाब देने होंगे.

सहयोगियों को एकजुट रखना- इस बार भाजपा के लिए एक और बड़ा मुद्दा होगा अपने सहयोगियों को एकजुट रखना. एनडीए के भीतर कई छोटे दल राज्यसभा सीटों के मुद्दे पर नाराजगी जता रहे हैं. इस प्रकार के दबाव का सामना भाजपा को करना पड़ेगा, और उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि गठबंधन में फूट न पड़े और सभी दल एकजुट रहें. यह चुनौती भविष्य में भाजपाकी राजनीति को प्रभावित कर सकती है.

> **जनरेशनल शिफ्ट और संगठन में बदलाव**
>
> भाजपा ने संकेत दिए हैं कि वह अपनी नेतृत्व शैली में एक जनरेशनल शिफ्ट की दिशा में बढ़ रही है. नितिन नबीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद पार्टी में नई पीढ़ी के नेताओं को सामने लाने की दिशा में कदम उठाए गए हैं. इस बदलाव के साथ एक बड़ी चुनौती होगी यह सुनिश्चित करना कि पार्टी में पुराने और बुजुर्ग नेताओं का समर्थन बना रहे, और नई टीम में युवाओं को भी प्रमुख स्थान दिया जाए.